भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1071

दिनांक 05 दिसम्बर, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट आवंटन

†1071. श्री विजय कुमार हाँसदाकः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए धनराशि के आवंटन के संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति द्वारा निर्धारित लक्ष्य क्या है;

(ख) स्वास्थ्य क्षेत्र पर बजट अनुमान (बीई) की तुलना में वास्तविक व्यय (एई) एवं प्रतिशत के रूप में इसके उपयोग की तुलना का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की स्वास्थ्य देखभाल को वैश्विक स्तर के मानकों के अनुरूप सुधारने एवं जनसंख्या वृद्धि दर के अनुपात में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए संसाधनों को बढ़ाने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 के अनुसार, स्वास्थ्य में सार्वजनिक निवेश 2025 तक सकल घरेलू उत्पाद के 2.5% तक पहुँचने की परिकल्पना की गई है। इस दिशा में सरकार की पहल भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमानों से स्पष्ट होती है, जहाँ कुल स्वास्थ्य व्यय (टीएचई) के प्रतिशत के रूप में स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च में वृद्धि हुई है, जो 2014-15 में 29.0% और 2021-22 में 48% थी। इसी के अनुरुप, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सरकारी स्वास्थ्य व्यय (जीएचई) 2014-15 में 1.13% से बढ़कर 2021-22 में 1.84% हो गया है। वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में जीएचई की हिस्सेदारी निम्नलिखित तालिका में दी गई है:

वित्तीय वर्ष	**सकल घरेलू उत्पाद के % के रूप में जीएचई**
2019-20	1.35
2020-21	1.60
2021-22	1.84

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आवंटन को प्राथमिकता देने और निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपने स्वास्थ्य बजट को कुल राज्य बजट का कम से कम 8% बढ़ाने का मामला राज्यों के साथ उठाया है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग (डीओएचएफडब्ल्यू) के लिए बजट आवंटन में 102.64% की वृद्धि हुई है, जो 2017-18 (बजट अनुमान) में 47,353 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025-26 (बजट अनुमान) में 95,957.87 करोड़ रुपये हो गया है।

इसके अलावा, 15वें वित्त आयोग ने 2020-21 से 2025-26 तक की अनुदान अवधि के लिए स्थानीय सरकारों के माध्यम से स्वास्थ्य हेतु 70,051 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान किया है। सरकार स्वास्थ्य बजट में आवंटन बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।

****